(iv) EXPLORING POTENTIALITIES OF EXPORTING GRANITE ROCKS FROM PALGHAT.

*SHRI V. S. VIJAYARAGHAVAN (Palghat): Palghat abounds in granite rocks. These rocks and a new charm to this beautiful area which lies against the background of the enhanting western ghats. These rocks are used for construction of beautiful mansions and are available in abundance and at cheaper cost.

According to the scientists, the granite rocks found in Palghat are as old and as hard as the rocks found in moon. That is to say, about 4500 million years' old. The experts are of the opinion that we can earn a lot of foregin exchange from these rocks if they are properly utilised.

In America, huge crosses and memorials are erected from marble stones. If, instead of marbles which undergo wear and tear fairly quickly, the possibilities are explored as to the use of these granite stones, then we will be able to export them on a large scale. At present, stones not of very great antiquity are being exported to foreign countries. If the granite stones of Palghat, which are better in terms of antiquity and hardness, are exported then we would be able to earn a large amount of foreign exchange.

Therefore, I request the Government to send a study team to Palghat immediately to ascertain the potentialities of export of these stones.

(v) DIFFICULTIES BEING FACED BY VILLAGERS LIVING ON THE BORDER BETWEEN BIHAR AND UTTAR PRADESH.

श्री रोत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:

गंगा और घाघरा के तटीय 50 किलोमीटर लम्बी एवं 10 किलोमीटर चौड़ी वलुआही क्षेत्र में 50,000 एकड़ भूमि गंगा की गहरी धारा के कटाव तथा बाढ़ के कारण बिहार एवं उत्तर प्रदेश के आर-पार आती जाती रहती है। इस क्षेत्र में पांच लाख किसान प्रान्तीय सीमा के हेर-फेर की समस्या में उलझते रहते है । यह एक शाश्वत समस्या बन गई है । यू० पी० एवं बिहार के किसान कौरव-पांडव की तरह सीमा पर महाभारत युद्ध करने पर उतारू रहते हैं । रबी फसल तैयार है। बिहारी किसानों को यदि शान्तिपूर्वक उन की खेती जमीनों से फसलों को काटने में सुरक्षा आश्वस्त नहीं की गई तो शांति भंग होने की हर संभावना दृष्टिगोचर हो रही है ।

बिहार सरकार ने यू० पी० सरकार के भू-अभिलेखों के आधार पर वहां के किसानों को मालगुजारी रसीदें दी और उन्हें वैधानिक अधिकारों की मान्यता दी । वे शान्तिपूर्वक फसलें लगा कर काट ले जाते हैं । दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने 144 गांवों के किसानों को न तो उनके वैधानिक अधिकारों को माना और न तो उन्हें मालगुजारी रसीदें ही जारी की । इस प्रकार उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 की खुली अवहेलना करा वर्षों से कर रही है, जिससे सीमावर्ती बलिया जिले और भोजपुर जिले के किसानों में जम कर संघर्ष की कई घटनायें घट चुकी हैं । फसल कटनी के समय यू० पी० के किसान बिहारी किसानों की फसलें बंदूक गोली की नोक पर काट लेते हैं, जिससे स्थिति विस्फोटक हो गई है ।

सम्प्रति बिहारी प्रभावित किसान अपने वैधानिक अधिकारों की मान्यता के लिए विगत 2 फरवरी, 1981 से बक्सर अनुमंडलाधिकारी के समक्ष भूख

*The original speech delivered in Malayalam.

[श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा]

हड़ताल एवं धरना पर हैं। विगत 10 वर्षों से दियारा क्षेत्र के नेनोजार, ऊपरपुर, केशीपुर, नगपुरा-मुगरोल, पदमपुर, केशापुर, राजपुर, डिमरीमुदा, सलेमपुर, सोहरा आदि में 50 से अधिक किसानों की हत्यायें हो चुकी हैं तथा सैकड़ों व्यक्ति बलिया पुलिस एवं किसानों के सशस्त्र हमले से घायल हो चुके हैं। अपहरण के क्रम में 100 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं तथा 500 लोगों पर 107 की धारा की कार्यवाही की गई है।

अतः गृह मंत्री का मैं व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रबी फसल कटनी के समय सीमा संघर्ष, हत्या, लूट, चोरी, डकैती, बलात्कार आदि रोकने के लिए बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम, 1968 की धारा 26 के अन्तर्गत ऋण देने के लिए एक शक्तिशाली आयोग का गठन करे तथा बिहार के प्रभावित किसानों की फसलों की शान्तिपूर्वक काटने के लिए अविलम्ब सुरक्षा की व्यवस्था की जाये। इसके साथ बिहार के किसानों को बिहार सरकार के द्वारा सुपुर्द किए गए भू-अभिलेखों के अनुसार यू० पी० सरकार मान्यता प्रदान कर मालगुजारी रसीदें निर्गत करके सीमांकन कार्य "सर्वे आफ इंडिया" से यथाशीघ्र करायें ताकि लाखों लोगों को लहुलुहान न होना पड़े और अपने स्वराष्ट्र के अन्तर्गत विदेशी नागरिकों की तरह व्यवहार के द्वारा एक दूसरे राज्यों के बीच गंभीर अराजकता का वातावरण पनपने से रोका जा सके।

(vi) DEMAND FOR CREATION OF "VISHAL GOMANTAK".

SHRI EDUARDO FALEIRO (Murmugao): Once again the demand for creation of a "Vishal Gomantak" has been raised. The move visualises a new state consisting of Goa and the areas which are the subject-matter of the boundary dispute between Maharashtra and Karnataka. This move is vehemently opposed by all sections of public opinion in Goa. The people of Goa had unequivocally demonstrated their desire to maintain their separate identity in the historic opinion poll held in 1966 and this unanimous feeling has since been voiced at every available opportunity. On the other hand, the Legislative Assembly of Goa has expressed the ardent aspirations of the local people for Statehood without addition to any other territories. The Goa Legislature has passed a unanimous resolution demanding Statehood on the lines of all other States of the Union. I reiterate this demand. This is a fervent aspiration shared by the entire people of Goa and is the common platform of all the political parties existing there.

12.56 hrs.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1980-81; DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1977-78; AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1978-79.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 1980-81 and also discussion and voting on the demands for Excess Grants in respect of the Budget (General) for 1977-78 and also for 1978-79.

Motions moved:

(i) "That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Amount shown in the Third Column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1981 in respect of the following demands